



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 2—फरवरी 8, 2019 (माघ 13, 1940)
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 2—FEBRUARY 8, 2019 (MAGHA 13, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 5 दिसम्बर 2018

सं. बैंविबिबीसी.आरईटी.सं.11 /12.02.001/2018-19—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 51 और धारा 56 के साथ पठित, धारा 24 की उप धारा 2ए, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 13 अक्टूबर 2016 की अधिसूचना बैंविबि.सं.आरईटी.14/12.02.001/2016-17 और दिनांक 04 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना बैंविबि.सं.आरईटी.91/12.02.001/2017-18 को अधिक्रमित करते हुए, रिज़र्व बैंक एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि:

- (i) निम्नलिखित तिथियों से प्रभावी होकर, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित), स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक भारत में आस्तियां (एसएलआर आस्तियों के रूप में संदर्भित) बनाए रखेंगे, जिनका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर, दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के, निम्नलिखित प्रतिशत से कम नहीं होगा:

(क) 5 जनवरी 2019 से 19.25 प्रतिशत

(ख) 13 अप्रैल 2019 से 19.00 प्रतिशत

(ग) 6 जुलाई 2019 से 18.75 प्रतिशत

(घ) 12 अक्टूबर 2019 से 18.50 प्रतिशत

(ड) 4 जनवरी 2020 से 18.25 प्रतिशत

(च) 11 अप्रैल 2020 से 18.00 प्रतिशत।

इसका मूल्यांकन समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार किया जाएगा; और

(ii) ऐसी एसएलआर आस्तियां निम्नलिखित द्वारा बनाए रखी जाएंगी:

अ. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित),स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक द्वारा निम्न रूप में-

(क) नकद; अथवा

(ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(1949 का 10) की धारा 5(छ) में यथापरिभाषित स्वर्ण, जिसका मूल्य-निर्धारण वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक न किया गया हो: अथवा

(ग) निम्नलिखित लिखतों [जिसे इसके बाद सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियाँ ("एसएलआर प्रतिभूतियाँ") कहा गया है] में से किसी में भाररहित निवेश, नामतः—

(1) बाजार उधार कार्यक्रम और बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत समय-समय पर जारी भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियाँ, या

(2) भारत सरकार के खजाना बिल; या

(3) बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत समय-समय पर जारी राज्य सरकारों के राज्य विकास ऋण (एसडीएल);

(घ) भारत से बाहर निगमित बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित जमा और भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ;

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अंतर्गत किसी अनुसूचित बैंक द्वारा बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित जमाशेष के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक में उसके द्वारा रखा गया कोई अन्य जमाशेष;

उपर्युक्त मद संख्या (ग)(1) से (3) तक में बताई गई लिखतें, जो रिवर्स रेपो के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्जित किए गए हैं, को एसएलआर आस्तियां बनाए रखने के प्रयोजन से एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शामिल किया जाएगा।

एसएलआर आस्तियां बनाए रखने के प्रयोजन से निम्नलिखित प्रतिभूतियों को भार-सहित नहीं माना जाएगा, नामतः-

(क) किसी अन्य संस्था में किसी अग्रिम या किसी अन्य ऋण व्यवस्था के लिए रखी गई प्रतिभूतियों का वह अंश जिस पर ऋण नहीं लिया गया है या आहरण नहीं किया गया है;

(ख) संबंधित बैंक के अपेक्षित एसएलआर पोर्टफोलियो में से निकाली गई (कार्व आउट की गई) प्रतिभूतियां, जो भारत में कुल एनडीटीएल के अनुमत प्रतिशत तक सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) से चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को सम्पाश्विक के रूप में दी गई हैं, और

(ग) चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलसीआर) के अंतर्गत चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए सम्पाश्विक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत प्रतिभूतियां।

आ. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों,राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा

(क) नकद; अथवा

(ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(छ) में यथापरिभाषित स्वर्ण, जिसका मूल्य निर्धारण वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक न किया गया हो: अथवा

(ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (क) में यथापरिभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियों में भाररहित निवेश:

जो लिखत प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्जित किए गए हैं, वे एसएलआर आस्तियां बनाए रखने के प्रयोजन से एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शामिल किए जाएंगे।

एसएलआर आस्तियां बनाए रखने के प्रयोजन से निम्नलिखित प्रतिभूतियों को भार-सहित नहीं माना जाएगा, नामतः—

(क) किसी अन्य संस्था में किसी अग्रिम या किसी अन्य ऋण व्यवस्था के लिए रखी गई प्रतिभूतियों का वह अंश जिसके विरुद्ध ऋण नहीं लिया गया है;

(ख) चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलसीआर) के अंतर्गत चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए सम्पाश्विक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत प्रतिभूतियां।

स्पष्टीकरण: इसमें प्रयुक्त और अनुबंध में पारिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उन्हें अनुबंध में दिया गया है।

2. दिनांक 13 अक्टूबर 2016 की अधिसूचना बैंवि.सं.आरईटी.14/12.02.001/2016-17 और दिनांक 04 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना बैंवि.सं.आरईटी.91/12.02.001/2017-18 का अधिक्रमण, किसी भी प्रकार रिजर्व बैंक के इस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालता है, जो उसे उक्त अधिसूचनाओं के प्रभावी होने के समय उनका उल्लंघन करने या अनुपालन में चूक होने पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के तहत कार्रवाई करने के लिए प्राप्त हैं।

सुदर्शन सेन
कार्यपालक निदेशक
अनुबंध

इस अधिसूचना के प्रयोजन से,

(क) निम्नलिखित द्वारा रखे जाने वाले "नकद"

i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों द्वारा

- हाथ में नकद,
- भारत के अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास चालू खाते में निवल शेष;
- भारत से बाहर निगमित बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित जमा;
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अंतर्गत किसी अनुसूचित बैंक द्वारा बनाए रखने के लिए अपेक्षित जमाशेष के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक में उसके द्वारा बनाकर रखा गया कोई अन्य जमाशेष;

ii) प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/ केंद्रीय सहकारी बैंक में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सहकारी बैंक, जो एक अनुसूचित बैंक है, द्वारा रखी जाने वाली हाथ में नकद
- ऐसा सहकारी बैंक, जो एक अनुसूचित बैंक न हो, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 18 के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत बनाए रखने के लिए अपेक्षित नकद अथवा जमाशेष के अतिरिक्त उसके द्वारा रखी गयी हाथ में नकद; तथा
- ऐसे सहकारी बैंक, जो एक अनुसूचित बैंक हों, के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अंतर्गत बनाए रखने के लिए अपेक्षित जमाशेष के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक में उसके द्वारा बनाकर रखा गया कोई अन्य जमाशेष;
- ऐसे सहकारी बैंक, जो अनुसूचित बैंक नहीं हैं, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत बनाए रखने के लिए अपेक्षित जमाशेष के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक में उसके द्वारा रखा गया कोई अन्य जमाशेष; तथा
- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित "चालू खातों में निवल शेष", जो उक्त धारा के अंतर्गत उनके द्वारा बनाए रखने के लिए अपेक्षित जमाशेष के अतिरिक्त होगा।

(ख) "वाणिज्यिक बैंक" का आशय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा (5ग) में निर्दिष्ट बैंकिंग कंपनी और जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, संबंधित नया बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं, से है।

- (ग) "चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलसीआर)" का आशय ऐसी सुविधा से है, जिसके द्वारा बैंकों को अपने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना के प्रयोजन से उनके द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों को स्तर 1 उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में एसएलआर की अनिवार्य अपेक्षाओं के भीतर एनडीटीएल के एक निश्चित प्रतिशत तक मान्यता देने की अनुमति दी जाएगी।
- (घ) "चलनिधि समायोजन सुविधा" का आशय होगा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित रेपो नीलामियां (चलनिधि अंतः क्षेपण के लिए) तथा रिवर्स रेपो नीलामियां (चलनिधि अवशोषण के लिए)।
- (च) "सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)" का आशय उस सुविधा से होगा, जिसके अंतर्गत पात्र संस्थाएं अपनी एसएलआर प्रतिभूतियों के विरुद्ध दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को उनके संबंधित एनडीटीएल के एक निश्चित प्रतिशत तक भारतीय रिज़र्व बैंक से चलनिधि सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
- (छ) "बाजार उधार कार्यक्रम" का आशय ऐसे घरेलू रुपया ऋण से होगा, जिसे भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जनता से जुटाया गया हो और जिसका प्रबंधन नीलामी अथवा इस संबंध में जारी अधिसूचना में यथा-विनिर्दिष्ट अन्य तरीके से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006, लोक ऋण अधिनियम, 1944 तथा उन अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित बाजार योग्य प्रतिभूतियां जारी करके भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाएगा।
- (ज) "अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक" का आशय होगा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में शामिल बैंकिंग कंपनी, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक, तदनु रूप नए बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 5th December 2018

No. DBR.Ret.BC No.11/12.02.001/2018-19—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 24 read with Section 51 and Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and in supersession of the notifications DBR.No.Ret.BC.14/12.02.001/2016-17 dated October 13, 2016 and DBR.No.Ret.BC.91/12.02.001/2017-18 dated October 04, 2017, the Reserve Bank hereby specifies that:

- (i) with effect from the dates given below, every Scheduled Commercial Bank (including RRBs), Local Area Bank, Small Finance Bank, Payments Bank, Primary (urban) co-operative bank and State and central co-operative banks shall continue to maintain in India assets (referred to as 'SLR assets') the value of which shall not, at the close of business on any day, be less than:
 - (a) 19.25 per cent from January 5, 2019
 - (b) 19.00 per cent from April 13, 2019
 - (c) 18.75 per cent from July 6, 2019
 - (d) 18.50 per cent from October 12, 2019
 - (e) 18.25 per cent from January 4, 2020
 - (f) 18.00 per cent from April 11, 2020.

of their total net demand and time liabilities in India as on the last Friday of the second preceding fortnight, valued in accordance with the method of valuation specified by the Reserve Bank from time to time; and

- (ii) such SLR assets shall be maintained by:

A. Scheduled Commercial Banks (Including Regional Rural Banks), Local Area Banks, Small Finance Banks and Payments Banks, as -

- (a) cash; or
- (b) gold as defined in Section 5(g) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) valued at a price not exceeding the current market price; or
- (c) unencumbered investment in any of the following instruments [hereinafter referred to as Statutory Liquidity Ratio securities ("SLR securities")], namely:—
 - 1) Dated securities of the Government of India issued from time to time under the Market Borrowing Programme and the Market Stabilization Scheme ; or
 - 2) Treasury Bills of the Government of India; or
 - 3) State Development Loans (SDLs) of the State Governments issued from time to time under the market borrowing programme;
- (d) the deposit and unencumbered approved securities required, under sub-section (2) of section 11 of the Banking Regulation Act, 1949(10 of 1949), to be made with the Reserve Bank by a banking company incorporated outside India;
- (e) any balance maintained by a scheduled bank with the Reserve Bank in excess of the balance required to be maintained by it under section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

The instruments referred to in items at (c) (1) to (3) above that have been acquired from the Reserve Bank under reverse repo, shall be included as SLR securities for the purpose of maintenance of SLR assets.

Following securities shall not be treated as encumbered for the purpose of maintenance of SLR assets, namely:—

- (a) securities lodged with another institution for an advance or any other credit arrangement to the extent to which such securities have not been drawn against or availed of;
- (b) securities offered as collateral to the Reserve Bank for availing liquidity assistance under Marginal Standing Facility (MSF), up to the permissible percentage of the total NDTL in India, carved out of the required SLR portfolio of the bank concerned; and
- (c) securities offered as collateral to the Reserve Bank for availing liquidity assistance under Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) .

- B. Primary (Urban) co-operative banks/ State co-operative banks and Central co-operative banks as—
- (a) Cash, or
 - (b) gold as defined in Section 5(g) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof, valued at a price not exceeding the current market price: or
 - (c) Unencumbered investment in approved securities as defined in section 5(a) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof:

The instruments that have been acquired from the Reserve Bank under reverse repo, shall be included as SLR securities for the purpose of maintenance of SLR assets.

Following securities shall not be treated as encumbered for the purpose of maintenance of SLR assets, namely:—

- (a) securities lodged with another institution for an advance or any other credit arrangement to the extent to which such securities have not been drawn against or availed of; and
- (b) securities offered as collateral to the Reserve Bank for availing liquidity assistance under Marginal Standing Facility (MSF), up to the permissible percentage of the total NDTL in India, carved out of the required SLR portfolio of the bank concerned;

Explanation: The words and expressions used herein and defined in the Annex to this notification, shall have the meanings respectively assigned to them in the Annex.

2. The supersession of the Notifications, DBR.No.Ret.BC.14/12.02.001/2016-17 dated October 13, 2016 and DBR.No.Ret.BC.91/12.02.001/2017-18 dated October 04, 2017 shall not in any manner affect the right of the Reserve Bank to take such action as is open to it under the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) for any contravention or default in complying with any requirements of the said Notifications when they were in force.

SUDARSHAN SEN
Executive Director

Annex

For the purpose of this notification,

- (a) “cash” to be maintained by:
 - i) Scheduled commercial banks (including Regional Rural Bank), Small Finance Bank, Payments Bank and Local Area Banks shall include,
 - cash in hand,
 - the net balance in current accounts with other scheduled commercial banks in India.
 - the deposit required under sub-section (2) of Section 11 of the Banking Regulation Act, 1949 to be made with the Reserve Bank by a banking company incorporated outside India;
 - ii) Primary (urban) co-operative bank/State Co-operative bank/Central Co-operative bank shall include:
 - Cash in hand maintained by a Co-operative bank, which is a scheduled bank
 - Cash in hand maintained by a Co-operative bank, not being a scheduled bank, in excess of the cash or balance required to be maintained under Section 18 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with Section 56 thereof; and
 - any balances maintained by a Co-operative bank, which is a scheduled bank, with the Reserve Bank in excess of the balance required to be maintained by it under section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
 - any balances maintained by a Co-operative bank, not being a scheduled bank, with the Reserve Bank in excess of the balance required to be maintained by it under Section 18 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with Section 56 thereof; and
 - “Net balances in current accounts” as defined in the Explanation to sub-section (1) of Section 18 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with Section 56 thereof, in excess of the balance required to be maintained by it under the said section.
- (b) “Commercial bank” shall mean a banking company as defined in section 5(c) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and includes the State Bank of India, a corresponding new bank and a Regional Rural Bank.

- (c) “Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio” shall mean facility whereby banks will be permitted to reckon government securities held by them up to a certain per cent of their NDTL within the mandatory SLR requirement as level 1 High Quality Liquid Assets (HQLA) for the purpose of computing their Liquidity Coverage Ratio (LCR).
- (d) “Liquidity Adjustment Facility” shall mean Repo auctions (for injection of liquidity) and reverse repo auctions (for absorption of liquidity) conducted by the Reserve Bank. .
- (e) “Marginal Standing Facility” shall mean the facility under which the eligible entities can avail liquidity support from the Reserve Bank against SLR securities, up to a certain per cent of their respective NDTL outstanding at the last Friday of the second preceding fortnight.
- (f) “Market Borrowing Programme” shall mean the domestic rupee loans raised by the Government of India and the State Governments from the public and managed by the Reserve Bank through issue of marketable securities, governed by the provisions of the Government Securities Act, 2006, Public Debt Act, 1944 and the Regulations framed under those Acts, through auction or any other method, as specified in the notification issued in this regard.
- (g) “Scheduled commercial bank” shall mean a commercial bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).